

20

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर ।
जयपुर विकास प्राधिकरण भवन ।

क्रमांक : झ.उ./नवि/91/

दिनांक : 11/7/91

विषय :- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम गजसिंहपुरा में भूमि अवाप्ति बाबत पृथ्वीराज नगर योजना

मुकदमा नम्बर :

1. 316/88

: : अ वा र्ड : :

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि को अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984) का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1 का धारा 4(1) के तहत क्रमांक : प. 6(15)नविआ/TA/87 दिनांक 6.1.88 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7 जुलाई, 1988 को कराया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम को धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प. 6(15)नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के द्वारा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम गजसिंहपुरा तहसील जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

क्र.सं.	मुकदमा नं.	खतरा नं.	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा बी. बि.	आवेदार् का नाम
1.	214/88	3/2	10-17	भवरी देवी धर्म पत्नीमन्नालाल तुराना सा.देह

मुकदमा नम्बर 214/88 खतरा नम्बर 3/2 :

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खतरा नम्बर 3/2 श्रीमती भवरी देवी धर्मपत्नी मन्नालाल तुराना सा.देह के नाम दर्ज हैं । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम को धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 7.3.91 को नोटिस दिये गये जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार आवेदार् नहीं मिला तथा आवेदारान के पति मिले तथा आवेदारान के पति ने नोटिस पढकर वापस देकर लेने से मना किया अतः बाद तामील पेश ही के साथ वापस लौटाये गये जो फाक्री में शामिल मिलल हैं ।

न.वि.प्रा. के आग्रह का कथन है कि आवेदारान को पुनः धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिये गये एवं समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाये । दिनांक 20.3.91 को पुनः धारा 9 एवं 10 के नोटिस आवेदारान को दिये गये जो तामील कुनिन्दा की हल्फिया

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

रिपोर्ट^{के} अनुसार परिवार के व्यक्त सदस्य को देकर तामोल करवाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 8.4.91 को बातेदार की ओर से उनके अभिमाधक श्री अनील मेहता उपस्थित हुये उनका कथन है कि श्रीमती भवरी देवी की मृत्यु हो चुकी है अतः उनके उत्तराधिकारी की ओर से वे बादमें कालातनामा पेश करेंगे। दिनांक 28.3.91 को दैनिक नवज्योति एवं राष्ट्रदूत समाचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। श्री मेहता समय समय पर उपस्थित होते रहे लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारीयो की ओर से कालातनामा एवं ब्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 3.5.91 को ज.वि.प्रा. के अभिमाधक ने बातेदारान के वारितान के नाम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिये जाने हेतु निवेदन किया है। दिनांक 9.5.91 को दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स में धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन मृगम मृतका के उत्तराधिकारीयो के नाम से करवाया गया। इसके उपरान्त श्री श्री मेहता धारा ना तो ब्लेम पेश किया और ना ही कालातनामा पेश किया है। अतः इनके विरुद्ध स्फुटरफा कार्यवाही जमल में लाई ब्रसखि है गह।

मुआवजा निर्धारण :

जहाँ तक पृथ्वीराजनगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प. 6/15/नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा की राशी का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराजनगर योजना के 22 ग्रामों में से कितनी भी ग्राम के मुआवजा की राशी का निर्धारण नहीं किया। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराली जाई। इसके उपरान्त समय समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराजनगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के कितनी भी बातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया गया।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उन में कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय राजस्त्रीयो द्वारा उक्त क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है। पृथ्वीराजनगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7.7.88 को हुआ था इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप प्रांतियों के यहाँ पृथ्वीराजनगर योजना के क्षेत्र में भूमिों की रजिस्ट्रेशन को क्या दर थी उत पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

जहाँ तक उपरोक्त बरत नम्बर के बातेदार को मुआवजे निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त मामले में स्फुटरफा कार्यवाही होने के कारण एवं बातेदार द्वारा कोई पेश नहीं करने के कारण बातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशी की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी नेपुरल जस्टीस के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्णय लिये मुआवजा अर्वाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जयपुर

विकास प्राधिकरण के तयिब ने ^{प्रपत्र} पत्र क्रमांक : टी.डी.आर./91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया गया है कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम गजतिंडपुरा में 18,600/-रु. प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था। इसलिये जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है।

हमने इस सम्बन्ध में उपां पुंजियक एवं तहसीलदार जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर श्री जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इतने अधिक नहीं थी। तहसीलदार जयपुर विगत प्राधिकरण [प्रथम] ने श्री अपने सु.ओ.नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा तहसील जयपुर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशी 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से अर्वाइ जारी किये गये एवं जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अमि. श्री के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशी 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ती नहीं होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से अर्वाइ पारित किये गये हैं।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशी 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी।

केन्द्रीय भूमि अर्वाइ अधिनियम के अन्तर्गत अर्वाइ पारित करने के लिये 2 वर्ष की समयवधी नियत है लेकिन बातेदारान/हितदारान को धारा 9 एवं 10 के अर्वाइ तामील कुनिन्दा, रजि. ए.डी. एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का धोतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते। इसलिये सकारणा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जहाँ तक पेड, पीछे, कृष एवं भूमि पक्ष की स्ट्रुक्चर का प्रश्न है बातेदारान/हितदारान द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीने पेश किये हैं। ऐसी स्थिति में ^{प्र. अ. अ.} स्ट्रुक्चर के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकी एवं अनुमोदित तकमीना प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जावेगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का अज्ञातान विधिक रूप से मालिकाना एक सम्बन्धी दस्तावेज पेश करने पर ही किया जावेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अर्वाइ का भाग है के अनुसार किया जा रहा है।

अतिरिक्त निदेशक ^{प्रथम} [तकम] एवं तक्षम अधिकारी भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पूरबीराजमगर योजना के तहत 22 ग्राम ^{अ. अ.} जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अन्तर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अन्तर अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अर्वाइ केन्द्रीय भूमि अर्वाइ अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23(1)-(2) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशी पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलिशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशी भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशी के साथ दर्शाया गया है।

यह अवार्ड आज दिनांक 1.7.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

संगन : परिशिष्ट "ए"



भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर।
जयपुर

यह अवार्ड आज दिनांक 31-7-91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F.6(15) गपिआ/87 पारित दिनांक 31-7-91 को अनुमोदन होकर पाला हुये है। रप.सश नम्बर 3/2 का अवार्ड आज दिनांक 31-7-91 को घोषित किया जाकर फाईल किया जाता है।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

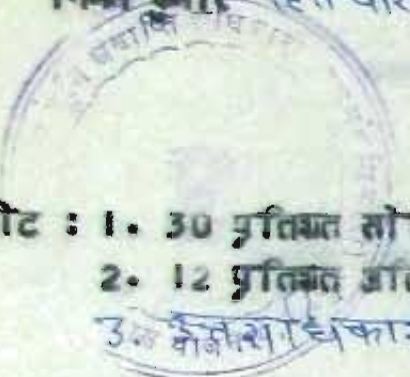
(Handwritten signature)

94

परिशिष्ट - ए - ग्राम गजसिंहपुरा

क्र.सं.	आवेदक/हितदार का नाम	क.न.	रकबा बी. वि.	भूमि के मुआवजे की दर	भूमि के मुआवजे की राशी	तोलिशियम राशी 30%	अतिरिक्त राशी 12%	कुल मुआवजा राशी
1.	मन्नालाल, विमल कुमार एवं निर्मल कुमार हितधारी	3/2	10-17	24,000.00	2,60,400.00	78120.00	93301.00	4,31,821.00
कुल राशी					2,60,400.00	78120.00	93301.00	4,31,821.00

नोट : 1. 30 प्रतिशत तोलिशियम वार्जेज कालम नं. 7 के आधार पर गणना की गई है ।
 2. 12 प्रतिशत अतिरिक्त वार्जेज राशी की गणना धारा 4(1) के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7-7-1988 से 1-7-1991 तक की गई है ।
 3. के.सि.सि. अधिकारी के प्रमाण पत्र पेश करने पर प्रवाड में से भु-प्रापका राशी देय होगी



भूमि अधिग्रहण अधिकारी
 नगर विकास सपरियोजनाएं, जयपुर ।
 जयपुर